(b) if so, what suggestions and observations were made at the meeting; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir, the Centre for policy Research organised a seminar on 4th January, 1996 on Comprehensive Test Ban Treaty negotiations and India's policy in this regard. Participants included a number of prominent scholars, former Ministers, retired service officers and civil servants. Some senior Government officials participated in their private capacity as observers.

(b) The seminar endorsed the Government's position as articulated in Prime Minister's speeches in Kuala Lumpur and NAM summit at Cartegna that India favours a truly comprehensive treaty that is an integral part of a phased, time-bound plan of total nuclear disarmament.

(c) Government have taken note of the views expressed by the participants.

Increase in the cost of passports

581. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the reasons for frequent increase in the cost of passports;

(b) the break-up of costs and increase thereof;

(c) whether Government would streamline the system of passport issuance in Andhra Pradesh; and

(d) if so, the steps proposed to be taken in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) and (b) After a period of 15 years, in July 1993, passport fee was revised from Rs. 50/to Rs. 300/for issue of a fresh passport keeping in view the increased cost of production and preparation of improved passport booklets; introduction of news procedures involving specialised equipment; and computerisation.

(c) and (d). In all passport offices, Government have and shall continue to take steps for expenditious issue of passports such as augmentation of staff strength, upgradation of office facilities including computerisation; review of systems and procedures in order to reduce delays; and regular inspections of passport offices and follow-up action.

चकमा शरणार्थियों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

582. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में चकमा शरणार्थियों की समस्या के समाधान हेतु सुझाव देने के लिए एक उच्च शक्ति सम्पन्न उप-समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति को निश्चित समयावधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था;

(घ) यदि हां, तो वह समयावधि क्या थी और क्या सरकार को वह प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या सुझाव दिए गए हैं और यदि सरकार को अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी): (क) से (ङ): अरुणाचल प्रदेश में चकमाओं तथा हाजोंगों के मुद्दे की समग्र पृष्ठ-भूमि की जांच के लिए तथा किस प्रकार की कार्रवाई की जाए, यह जानने के लिए 29 दिसम्बर, 1995 को एक उच्च स्तरीय ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप की संरचना इस प्रकार है:-

(i) श्री एस.बी. चव्हाण, अध्यक्ष, गृह मंत्री।

(ii) श्री सैयद सिब्ते रजी, गृह राज्य मंत्री।

(iii) श्री एच. आर. भारद्वाज, राज्य मंत्री विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मामले।

(iv) श्री गेगांग अपांग, मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश।

(v) श्री वी.के. जैन, विशेष सचिव (आई.एस.पी.) गृह मंत्रालय।

(vi) श्री बी.एन. झा, संयुक्त सचिव (एन.ई.) गृह मंत्रालय।

(vii) श्री डी.सी. सांखला, गृह आयुक्त अरुणाचल प्रदेश सरकार।

(viii) श्री के.ए. प्रभाकर राव, विधि सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार।

5.1.1996 को आयोजित, उच्च स्तरीय ग्रुप की पहली बैठक में ऐसी कार्रवाई जो इस समस्या के समाधान के लिए तुरन्त की जा सके, सुझाने के लिए अधिकारिक स्तर की एक उप समिति की स्थापना का निर्णय लिया गया था। उप-समिति की संरचना इस प्रकार से है:—

(i) श्री वी.के. जैन, विशेष सचिव (आई.एस.पी.) गृह मंत्रालय।

(ii) श्री अरविंद वर्मा, विशेष सचिव (सी.एस.) गृह मंत्रालय।

(iii) डा. एस. सी. जैन, संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय।

(iv) श्री डी.सी. मिश्रा, मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार।

(v) श्री डी.सी. सांखला, गृह आयुक्त अरुणाचल प्रदेश सरकार।

(vi) श्री के.ए. प्रभाकर राव, विधि सचिव अरुणाचल प्रदेश सरकार।

दिनांक 9.1.1996 के अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि राज्य के अंदर रह रहे प्रत्येक चकमा के जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और कि, कानून के अनुसार उठाए गए किसी कदम के अलावा, चकमाओं को उनके घरों से निकाला नहीं जाएगा।

राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि उक्त उच्च स्तरीय ग्रुप और उप-समिति अपना काम जारी रख सकती है परन्तु यह काम, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए, न कि उसके उल्लंघन स्वरूप राज्य सरकार से उप-समिति का काम जिसमें राज्य का एक दौरा भी शामिल है, जारी रखे जाने में उनकी सुविधा के बारे में पूछा गया है।

BIDS for Basic Telecom Service in Maharashtra

583. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of COMMUNICATION be pleased to state:

(a) the details of the dispute about the bids in Maharashtra for the basic telecom tender;

(b) what was the approach of the TEC in tender evaluation for this State, what were the allocation of points for different parameters allotted by the TEC to each bidder; and

(c) the revised considerations adopted by the Chairman, Telecom Commission and Member, Finance, subsequently accepted by Government and what were the different parameters allotted by them?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) One of the bidders, M/s. Tata Tele Services Ltd. has filed a petition in the Bombay High Court challenging the validity of the decision to award the licence to another bidder, i.e. M/s. Hughes Ispat Ltd. The case is still sub-judice.

(b) TEC calculated the marks far DELs (Direct Exchange Lines) on the basis of projection for three years while marks for Village PTs (VPTs) as a percentage of DELs were awarded for the first year only.

(c) While considering the TEC report, Chairman, Telecom Commission and Member (Finance), decided that marks for DELs and for VPTs as a percentage of DELs should be calculated on same time scale of three years. This resulted in change of marks allotted to each bidder.

Misuse of Power by Sub-Postmaster in Punjab

584. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the agents of small savings schemes, viz. PPF, NSC, NSS, KVIP etc. against the alleged misuse of power, corruption, harrasment and misbehaviour of Sub-Postmaster of Sector 59, Phase V, SAS Nagar (Mohali), District Ropar (Punjab) particularly towards the women agents engaged in the promotional business of the above small saving schemes;

(b) if so, the details thereof; and whether Government have made any enquiry into the allegations and if so, the results thereof; and

(c) the action Government have so far taken or propose to take in the matter?